



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 922 राँची, गुरुवार, 9 अग्रहायण, 1939 (श०)  
30 नवम्बर, 2017 (ई०)

#### खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

-----  
अधिसूचना  
27 दिसम्बर, 2016

**संख्या- 06/उप.फो. (संरक्षण परिषद् चयन) 06/2015 खा.आ. - 5300--** विभागीय संकल्प संख्या:- 2954, दिनांक 4 जून, 2015 के आलोक में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा राज्य सरकार झारखण्ड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन विभागीय अधिसूचना संख्या 1019, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा किया गया है। इसमें से कुछ गैर सरकारी सदस्यों के पद त्याग/पदच्युत होने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या 1019, दिनांक 15 मार्च, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए झारखण्ड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का निम्नवत् पुनर्गठन किया जाता है:-

- (क) माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,  
झारखण्ड, - अध्यक्ष ।
- (ख) प्रधान सचिव/सचिव,  
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,  
झारखण्ड, राँची - सदस्य सचिव ।

(ग) राज्य सरकार के विभाग/स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधि (जो परिषद् के पदेन सदस्य होंगे):-

- i- प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखण्ड ।
- ii- प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड ।
- iii- प्रधान सचिव/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड ।
- iv- प्रधान सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड ।
- v- प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड ।

(घ) गैर सरकारी सदस्य

क्र.सं.	नाम	पता
i	श्री प्रिंस कुणाल	डी.टी. 1108, डैम साईड, धुर्वा, राँची ।
ii	श्री राकेश कुमार सिंह	फ्लैट नं०- 2 , अम्पाली एपार्टमेंट, निवारणपुर, राँची ।
iii	श्री अनिल कुमार सिंह	जीवन, बस्ताकोला, धनसार, धनबाद, पिन-828106 ।
iv	श्री अरविन्द सिंह	ग्राम-सिरहा, पो-उंटारी रोड, थाना-उंटारी रोड, जिला-पलामू ।
v	श्री एच.एन.राम	पिता-स्व. मुखलाल राम, मकान नं-301, तृतीय तल्ल, राधा ब्लॉक, हेभन रिभरब्यू हरिओम नगर, रोड नं०-05, आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावाँ, 831013 ।

(ड.) व्यक्तिगत उपभोक्ता कार्यकर्ता (जो किसी भी उपभोक्ता संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं)

- i श्रीमती मीना कुमारी ए.-2, सिन्हा अपार्टमेंट, मनोरमा नगर, एल०सी० रोड, धनबाद।

2. राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् से संबंधित शर्तें एवं नियम:-

- (क) परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना संख्या 1019, दिनांक 15 मार्च, 2016 की तिथि से 3 (तीन) वर्षों का होगा। तीन वर्षों के उपरांत परिषद् का पुनर्गठन किया जायेगा । किसी भी सदस्य का स्थान रिक्त रहने पर परिषद् के कार्य या निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
- (ख) क्रमांक (1) के (घ)/(ड.) के सदस्यों सरकार के द्वारा निम्न प्रकार के आरोप साबित पाये जाने पर हटाया भी जा सकता है:-
  - (i) राजनीतिक सम्बद्धता होने पर ।
  - (ii) अपराधिक गतिविधि में आरोप पत्र दाखिल होने या दोष-सिद्ध होने पर ।
  - (iii) अनुत्तरदायी और उपभोक्ता विमुख व्यवहार होने पर ।

- (iv) गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने पर ।
  - (v) चिकित्सीय अक्षम होने पर ।
  - (vi) उपभोक्ता कानून एवं मुद्दों की कम जानकारी होने पर ।
  - (vii) परिषद् की दो लगातार बैठकों में अनुपस्थित होने होने पर ।
- (ग) परिषद् के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने उक्त पद पर हैं, जिसके कारण वे परिषद् के सदस्य मनोनीत किये गये हैं ।
- (घ) सदस्यों का कार्यकाल मात्र 3 वर्ष का होगा । 3 वर्ष के बाद पुनः चयन किया जा सकता है, परन्तु चयन प्रक्रिया में फिर से शामिल होना पड़ेगा । कोई भी गैर-सरकारी सदस्य दो बार से अधिक चयनित नहीं हो सकता है ।
- (ङ) सरकारी पदाधिकारी को छोड़कर अन्य संस्थान के लोग अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे सकेंगे ।
- (च) प्रत्येक तीन माह (त्रैमासिक) में कम से कम 1 बार परिषद् की बैठक अवश्य होनी चाहिए। अध्यक्ष/सचिव चाहें तो कभी भी आपातकालीन बैठक बुला सकते हैं ।
- (छ) प्रत्येक बैठक से 15 दिन पूर्व सभी संबंधितों एवं सदस्यों को सूचना दी जायेगी, जिसका अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा अनुपालन कराया जायेगा ।
- (ज) बैठक का एजेन्डा अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य सचिव तैयार कर बैठक के समय पटल पर रखेंगे ।
- (झ) बैठक में कम से कम 10 प्रतिशत सदस्यों का होना गणपूर्ति (कोरम) के लिए आवश्यक होगा।

### 3. राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकलाप:-

- (क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में परिषद् कार्य करेगी । परिषद् का कार्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा एवं बढ़ावा देना होगा । यथा:-
- (i) सामान एवं सेवाओं के वैसे विपणन जो जीवन और सम्पत्ति के लिए खतरनाक हैं, के खिलाफ उपभोक्ताओं की रक्षा का अधिकार ।
  - (ii) वस्तुओं व सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और मूल्य के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ उपभोक्ता की रक्षा का अधिकार की सूचना ।
  - (iii) जहाँ तक संभव हो, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर माल एवं सेवाओं के प्रकार की जानकारी का अधिकार ।
  - (iv) उपभोक्ता की हितों की उचित फोरमों में सुनवाई का अधिकार ।
  - (v) अनुचित व्यापार व्यवहार या अवरोधक व्यापारिक व्यवहार या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के खिलाफ निवारण का अधिकार ।
  - (vi) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार ।
- (ख) राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, जिला उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से जनता की सहभागिता कर उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन को स्थापित करने के लिए कदम उठायेगा ।

(ग) राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् द्वारा प्रत्येक 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस एवं 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को समारोहपूर्वक मनाया जायेगा ।

4. परिषद् के सदस्य के रूप में पदेन सरकारी कर्मचारियों को उसी दर पर यात्रा-भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा, जो उन्हें पदस्थापित पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वेतनादि प्राप्त होने वाले शीर्ष से निकासी करेंगे ।
5. परिषद् के सदस्य के रूप में गैर सरकारी सदस्य को उसी यात्रा-भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के श्रेणी-पू के पदाधिकारी को अनुमान्य है तथा प्रति बैठक 500/- (पाँच सौ) रुपये दैनिक भत्ता के रूप में उन्हें देय होगा । इनका भुगतान 3456-सिविल पूर्ति-उप शीर्ष-02 से होगा ।
6. केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वैसे सदस्य जो इस राज्य के होंगे, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे । इसी प्रकार राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य अपने संबंधित जिलों के परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे ।
7. सरकार को आवश्यकतानुसार परिषद् भंग करने या नियमों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**विनय कुमार चौबे,**  
सरकार के सचिव ।

-----